



International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2025; 8(1): 01-09
www.theeconomicsjournal.com
Received: 01-10-2024
Accepted: 04-11-2024

शीलु कुमारी
अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान
संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल
विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

कुटीर एवं लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता: रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव

शीलु कुमारी

DOI: <https://doi.org/10.33545/26179210.2025.v8.i1a.442>

सारांश

भारत के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता को एक लंबे अरसे से महसूस किया जा रहा है। समानता का आधार आर्थिक और सामाजिक दोनों का होना अनिवार्य है। गहराई से देखने पर ही इस बात को समझा जा सकता है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए महिलाओं को दोनों ही स्तरों यानी कि आर्थिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त करना होगा। अधिकांशतः महिलाओं से पक्षपात को आर्थिक या स्त्री-पुरुष के पारस्परिक संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। वास्तव में तो लैंगिक भेदभाव एक ऐसा विषय है, जिसमें सोचे-समझे ढंग से ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाती है, जिससे महिलाओं को अलग, वंचित और हाशिए पर रखा जा सके। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है। देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, स्टार्टअप इंडिया भारत में पहलों, योजनाओं, नेटवर्क और समुदायों को सक्षम बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना रोजगार सृजन और नवाचार के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, तथा आय असमानता और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाती हैं। भारतीय समाज में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चों पर बदलाव लाने की जरूरत है। भारत में महिला उद्यमिता रोजगार का एक बड़ा स्रोत हो सकती है। उदारवादी नारीवादी सैद्धांतिक लेंस के माध्यम से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि भारत में सफल महिला उद्यमिता के लिए कुछ आधार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है। समाज का अधिकांश हिस्सा महिलाओं के काम करने और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के अधिकारों को मान्यता नहीं देता है, और ये दृष्टिकोण बहुत गहरे हैं। महिला उद्यमियों की क्षमता को मजबूत करना भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन यह केवल व्यापक सामाजिक सुधारों के हिस्से के रूप में ही संभव हो सकता है।

कूटशब्द: महिला उद्यमिता, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सामाजिक समानता

प्रस्तावना

दुनिया अब 8 बिलियन लोगों का समुदाय है, जिसमें चीन के बाद भारत की आबादी दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की जनसंख्या की कहानी में एक खास बात जनसांख्यिकीय लामांश का अनूठा लाभ है। अगर इस

Corresponding Author:
शीलु कुमारी
अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान
संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल
विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह देश को वैश्विक शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालाँकि, भारत की विकास कहानी, कुल मिलाकर, पुरुष प्रधान रही है। दुर्भाग्य से, रोजगार सृजन दर जनसंख्या वृद्धि दर से आगे निकल गई है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक बेरोजगारी और अल्परोजगार है। उद्यमिता इस अंतर को पाटने का एक व्यवहार्य समाधान है क्योंकि यह युवाओं के लिए आजीविका उत्पन्न करता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो सामाजिक जनसांख्यिकीय मापदंडों में सुधार से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कोई वृद्धि हुई है और न ही इससे उनका विकास हुआ है। वास्तव में, भारत कार्यबल में महिलाओं की सबसे कम भागीदारी वाले देशों में से एक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि महिला स्नातकों के अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में बेरोजगार होने की संभावना 3.5 गुना अधिक है। बिना किसी सुधारात्मक कार्रवाई के समय के साथ इन आंकड़ों में वृद्धि होने की उम्मीद है। महिला उद्यमिता पर एक बैंक एंड कंपनी की रिपोर्ट भविष्यवाणी करती है कि भारत की कामकाजी उम्र की आबादी 2030 तक एक अरब तक पहुँच जाएगी, जिसमें 54 मिलियन महिलाओं के कार्यबल में प्रवेश होगा, जिससे अकेले महिलाओं के लिए 400 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

बेरोजगारी की समस्या को दूर करने, उनकी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और आर्थिक विकास में योगदान देने में महिला उद्यमिता की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। महिला उद्यमिता को मुख्यधारा में लाने से अधिक जागरूक प्रजनन विकल्प, उच्च शिक्षा और स्वयं तथा परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य को सक्षम करके गुणक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, महिलाओं की भूमिका सहानुभूति-आधारित संस्थानों को बढ़ावा देने में सर्वोपरि है जो लोगों पर केंद्रित हैं और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हैं (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-26)। यह उत्साहजनक है कि इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई क्षेत्र से 25 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व में होना चाहिए। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, GIZ के सहयोग से, महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए नए व्यवसाय शुरू करने और मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने के लिए इनक्यूबेशन और त्वरण कार्यक्रम प्रदान करता है, जो महिला उद्यमों के आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्ट-अप योजना के हिस्से के रूप में है (अब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-10)।

पिछले कुछ वर्षों में महिला-केंद्रित इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और वेंचर कैपिटल फर्मों का उदय भी हुआ है। शीकैपिटल, वूमेनोवेटर और बिल्ट बाय गर्ल्स जैसे उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को अपने

व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाकर महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। हालाँकि, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 में महिला उद्यमशीलता गतिविधि में भारत 43 में से 41वें स्थान पर है। भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक महिला उद्यमों का घर है; हालाँकि, ये कुल संख्या का केवल 20 प्रतिशत है (अब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-10)। इस समस्या का मूल कारण वित्त तक सीमित पहुँच है। महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विविध और अनुकूलित उत्पादों तक पहुँच की आवश्यकता है। इसके अलावा, संपार्श्विक और अत्यधिक दस्तावेज जैसी प्रक्रियागत आवश्यकताएं ऋण तक उनकी पहुँच को सीमित करती हैं। पुरुष-प्रधान समाज होने के कारण, पुरुष ही संपत्ति के प्राथमिक स्वामी होते हैं, जो महिलाओं की वित्त में उनका उपयोग करने की क्षमता में बाधा डालता है। लैंगिक रुढ़िवादिता जो घरेलू कर्तव्यों को महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी मानती है, कम वित्तीय साक्षरता और सलाह और सहायता के अवसरों तक सीमित पहुँच अन्य चुनौतियाँ हैं (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। हमारा देश अभी इस मामले में पीछे है, और यहाँ महज 27 प्रतिशत महिलाएं ही कामकाजी हैं। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, देश में लंबे समय से चली आ रही प्राथमिकता है। धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी यह एक आवश्यक कदम होना चाहिए। महिला उद्यमिता को ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान की कारगर रणनीति के रूप में देखा जाने लगा है (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-14)। देश में आर्थिक विकास और स्थिरता में सुधार के पीछे महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोतरी होना एक प्रमुख कारण है। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने को प्रेरित करती है। इससे महिलाओं के लिए और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे अंततः श्रमशक्ति में स्त्रीशक्ति में स्त्री-पुरुष असमानता कम करने में मदद मिलती है। महिला उद्यमिता से परिवार और समाज में आर्थिक खुशहाली लाने, गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण में ज़रूरत मदद मिलता है (अब्जर्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

ऐसे समय जब विविधता पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है और महिलाओं को अज्ञात बाधाओं से निबटकर उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत की आधी आबादी का हिस्सा महिलाओं का है और महिला उद्यमियों की संख्या में बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाया जा सकता है। इससे ना सिर्फ़ विकास की रफ़्तार तेज़ होगी, बल्कि आदि आबादी को रोजगार भी मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाने के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना अपरिहार्य है। वर्तमान समय में कुटीर एवं लघु उद्योगों में महिला उद्यमिताओं की संख्याओं में

अत्यधिक वृद्धि हो रही है (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2020, पृष्ठ संख्या-23)। महिला उद्यमिता की निर्णय अवसर और क्षमता में वृद्धि हो रही है। बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता को रोजगार सृजन के रूप में देखा जा रहा है।

निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के बीच बहुत विकास हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जागरूकता पैदा की जाए, मौजूदा पहलों को स्पष्ट किया जाए, विभागों को एक साथ लाया जाए, साझेदारों को जोड़ा जाए, इन सभी प्रयासों को समेकित किया जाए और उनका लाभ उठाया जाए। महिला उद्यमियों के तेजी से उभरते समूह से प्रोत्साहित होकर नीति आयोग एक समर्पित महिला प्रकोष्ठ शुरू किया है, ताकि उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान किया जा सके, जहां विभिन्न हितधारक अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए जुड़ सकें (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा भारत से महिला उद्यमियों के एक प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह कहा कि महिला उद्यमी प्रकोष्ठ समावेशी आर्थिक विकास करने का प्रस्ताव रखता है (अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-1)। भारत में महिलाओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भूमिका निभाई है। आज जब आप उस भूमिका का आधुनिकीकरण करते हैं और उसे उद्यमिता का रूप देते हैं और उसे सुविधा प्रदान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित काम देखेंगे। आज भारत में हो रहे संरचनात्मक और परिवर्तनकारी सुधारों में उच्च स्तर का विश्वास है। इस विश्वास को मज़बूत करने में महिला उद्यमिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा SALT-mysaltapp के सहयोग से प्रकाशित श्वेत पत्र के अनुसार, भारत के टियर 2 और 3 शहरों में केवल तीन प्रतिशत महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए बैंक ऋण या इक्विटी निवेश जैसे बाहरी वित्तपोषण तक पहुंच है। इस पत्र में महिला उद्यमियों के खतरों और उद्योग में समान अवसर की कमी पर प्रकाश डाला गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के 'एट द हेल्म: वूमैन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया' शीर्षक वाले इस अध्ययन का उद्देश्य टियर 2 और 3 शहरों के रूप में परिभाषित मध्य भारत में महिलाओं की उद्यमिता को प्रभावित करने वाली जटिल सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को समझना था (भारतीय रिजर्व बैंक रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-1)। यह अध्ययन 30 शहरों में 300 महिलाओं की भागीदारी के साथ किया गया था, जिसमें कम से कम तीन साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले और 10 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया गया था (फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमैन एंटरप्रेन्योर्स (FIWE) 2024, पृष्ठ संख्या-1)। सभी मामलों में, साक्षात्कार की गई महिलाएँ या तो खुद संस्थापक थीं, या पारिवारिक व्यवसाय में पूर्णकालिक, निर्णय लेने वाली भूमिका निभा रही थीं।

इस शोधपत्र में लिंग-विभाजित आंकड़ों की कमी के कारण गंभीर सूचना अंतराल पाया गया। रूढ़िवादिता का मुकाबला करने, इस वर्ग में रुचि पैदा करने और आंकड़ों के आधार पर प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्ययन में कहा गया है कि लड़कियों के लिए उच्च STEM और स्नातकोत्तर शिक्षा में देश की उपलब्धियों को देखते हुए, यह प्रवृत्ति चौंकाने वाली है। आशावादी रूप से, शोधपत्र में पाया गया कि नमूना शिक्षित महिला उद्यमियों का एक विविध समूह है, जिसमें 14 प्रतिशत के पास स्नातक की डिग्री है और 55 प्रतिशत ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जो पेशेवर पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाता है। हालाँकि, कई अन्य जिम्मेदारियों के कारण, कई उद्यमी 30 से 60 वर्ष की आयु के बीच हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि महिलाओं को देर से सफलता मिलती है (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2024, पृष्ठ संख्या-42)।

यह भी एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में उनके द्वारा उद्यमशीलता के जोखिम उठाने और व्यवसाय स्थापित करने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने से सीधे तौर पर एक अधिक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में योगदान मिल सकता है। देश में समावेशी और समृद्ध उद्यमशील परिदृश्य के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए लिंग-संवेदनशील नीतियों को बनाने और संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, पूंजी, कौशल विकास और मजबूत सामुदायिक नेटवर्क अभिसरण शामिल है। टियर-2 शहरों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र तैयार है, और वर्तमान में महिलाएं जो विविध प्रकार के व्यवसाय चला रही हैं, वे आशाजनक हैं। स्थानीय स्तर पर तैयार होने के अलावा, महिला प्रतिभाएं विवाह-संबंधी प्रवास के हिस्से के रूप में भी इन शहरों में आती हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, वे उद्यमी करियर पर विचार करने के लिए तैयार होती हैं, जिन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है (फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमैन एंटरप्रेन्योर्स (FIWE) 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमिता का योगदान

उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति ने देश में महत्वपूर्ण व्यावसायिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यावसायिक उद्यम देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय बदलाव लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके समाज में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ, स्टार्टअप इंडिया पहलों, योजनाओं, सक्षम नेटवर्क और समुदायों के निर्माण और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विविध हितधारकों के बीच साझेदारी को सक्रिय करने के माध्यम से भारत में महिला

उद्यमिता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टार्टअप में वैश्विक उछाल के बीच, भारत उद्यमशीलता के प्रयासों के एक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिसमें महिला उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान है (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में यह परिवर्तन महिलाओं के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है जो देश में उद्यमिता की कहानी को नया रूप दे रही हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की 73^{वें} दौर की रिपोर्ट (जुलाई 2015 से जून 2016) के अनुसार, कुल असंगठित गैर-कृषि स्वामित्व उद्यमों में से 19.5 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जिनमें 22 से 27 मिलियन लोग कार्यरत हैं। नीति आयोग की वेबसाइट पर अक्टूबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट "भारत में महिला उद्यमियों को सरकारी सहायता की व्याख्या" के अनुसार, भारत में महिलाओं का आर्थिक योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 17 प्रतिशत है (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। महिला उद्यमिता की वैश्विक रैंकिंग पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। हालाँकि, एक निजी अध्ययन "मास्टरकार्ड इंडेक्स ऑफ़ वूमन एंटरप्रेन्योर्स 2021" में भारत को कुल 65 देशों में से 57वें स्थान पर रखा गया है। सूचकांक तीन घटकों को बनाने के लिए 12 संकेतकों का उपयोग करता है: महिलाओं की उन्नति के परिणाम; ज्ञान संपत्ति और वित्तीय पहुँच और सूचकांक के निर्माण के लिए उद्यमशीलता सहायक स्थितियाँ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2019 में प्रकाशित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में ऋण तक पहुँच को महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में पहचाना गया है। महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को क्रियान्वित करता है, जो एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए अधिक सब्सिडी दी जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), जिसे एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, असेवित, अल्पसेवित और वंचितों के लिए वित्त तक पहुँच बनाना, नई पीढ़ी के उद्यमियों को पारंपरिक उधारदाताओं से वित्त

की उपलब्धता बनाना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र सदस्य ऋण संस्थान [एमएलआई] द्वारा दी जाने वाली संपार्श्विक और/या तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधाओं को गारंटी कवर प्रदान करना है (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

सीजीटीएमएसई ने महिला उद्यमियों के लिए ऋण की गारंटी कवरेज की सीमा को बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है। महिला उद्यमियों को अतिरिक्त रियायत के रूप में, सीजीटीएमएसई ने वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की कमी की है। मंत्रालय एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए कई अन्य योजनाएं भी क्रियान्वित करता है, जिनमें महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई भी शामिल हैं, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई), खरीद और विपणन सहायता योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) आदि (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी है। भारत में महिलाएँ परिवार की आधार हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की पहल एवं योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक गतिविधि में भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उद्यमिता विकास और आय अर्जक गतिविधियाँ व्यावहारिक साधन मुहैया करवाती हैं। कुटीर और लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि महिला उद्यमिता का प्रभाव चैन रीएक्शन की तरह होता है (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2024, पृष्ठ संख्या-42)। यानी कि महिला उद्यमिता से आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है और रोजगार सृजन में सहायता मिलती है। लघु वित्त के साथ स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला उद्यमिता गरीबी मिटाने और हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिला उद्यमिता की अवधारणा एक वरदान है। महिला उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और समाज में उनको सम्मान मिला है।

वर्तमान समय में भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। कुटीर एवं लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता महिला सशक्तिकरण को मजबूत और लैंगिक असमानताओं को दूर कर रही है। कुटीर एवं लघु उद्योग बड़े पैमाने पर व्यापार उद्यम को भी बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के ज़रिए रोजगार सृजन के ज़रिए गरीबी को कम करना है। कुटीर एवं लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता को नाबाई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय ऋण प्रदान करता है। महिला उद्यमियों का महत्व यह है कि वे अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वे आगे आएं और समान अवसरों का लाभ उठाएं (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2024, पृष्ठ संख्या-42)।

महिलाओं की उधमशीलता और आर्थिक भागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए और देश के आर्थिक विकास और समृद्धि को संभव बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नीतिगत कार्यक्रमों के ज़रिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किया जाए। सरकार ऋण, नेटवर्क, बाज़ार और प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान कर के महिलाओं को अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में लाने का प्रयास कर रही है। सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग विकास संगठन, विभिन्न राज्य लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक और उधमिता विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न सरकार संगठन अनेक कार्यक्रम चला रहा है (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। उधमिता विकास कार्यक्रम भी इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य उन प्रभावशाली महिला उधमियों की मदद करना है जिन्हें उचित अवसर की ज़रूरत है। महिला उधमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्कृष्ट महिला उधम देने की शुरुआत भी की गई है। महिलाओं के आय अर्जक को बढ़ावा देने के लिए महिला उधमी प्रोत्साहन कक्ष की स्थापना की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी बैंक) महिला उधमिता के लिए दो विशेष योजनाएँ चला रही है (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इसमें से योजना महिला उधम निधि है जो महिला उधमी को इक्विटी प्रदान करता है। दूसरी योजना महिला विकास निधि है जो आय अर्जक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। सिडबी बैंक बैंक महिला उधमियों को आसान शर्तों पर अनौपचारिक तरीके से ऋण प्रदान करता है। इसके साथ ही सिडबी बैंक महिला उधमियों को प्रशिक्षण भी देता है। केंद्रीय सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के तहत भी महिला उधमी को अनुदान उपलब्ध है।

महिला उधमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार स्टार्ट अप्स इंडिया योजना के तहत महिला उधमियों को प्रोत्साहन दे रहा है। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। तब से इसके माध्यम से महिला उधमियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह योजना एक समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला उधमियों को व्यापक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन जिसे स्टेप कार्यक्रम के नाम भी जाना जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित है (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिलाओं का दक्षता विकास किया जाएगा। यह कार्यक्रम कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हैंडलूम इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को दक्षता प्रदान करता है। स्टैंड अप कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में हुआ था। इस कार्यक्रम का वंचित समूहों को ऋण प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के द्वारा महिला उधमियों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत महिला उधमियों को दस लाख से लेकर एक करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है। परम्परागत उद्योगों के पुनरुत्थान के

लिए कोष जुटाने की योजना के अंतर्गत परम्परागत क्षेत्रों में निर्माण समूह बनाकर दस्तकारों को रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। इस योजना के तहत हस्तकला, हथकरघा, कोयर, कृषि प्रसंस्करण जैसे परम्परागत क्षेत्रों को कवर कर के 1.49 महिला दस्तकारों को सुविधा मुहैया करायी गई है। महिला उधम नीति के तहत महिला उधमियों को इक्विटी प्रदान करती है (कुरुक्षेत्र मैगज़ीन 2020, पृष्ठ संख्या-11)। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है, अभूतपूर्व उछाल देख रहा है, जिसमें महिला उधमी इस उछाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कई चुनौतियों को पार करते हुए और अवसरों का लाभ उठाते हुए, ये महिलाएँ न केवल उधमशीलता के परिदृश्य को आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि इसके भीतर गहरे बदलाव भी ला रही हैं। भारत की स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट (WISER) की एक रिपोर्ट में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों में काफी वृद्धि को दर्शाता है (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2024, पृष्ठ संख्या-1)। यह उछाल 2017 में महिला संस्थापकों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के मात्र 10 प्रतिशत से हाल के वर्षों में उल्लेखनीय 18 प्रतिशत तक एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह वृद्धि महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा, पूंजी तक बेहतर पहुँच और महिला उधमिता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने वाली सहायक सरकारी नीतियों का प्रमाण है।

अर्थव्यवस्था पर महिला उधमियों का प्रभाव बहुत बड़ा है, उनके उधम देश में लाखों व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। महिलाओं द्वारा संचालित उधम 27 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देते हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं (विश्व बैंक 2024, पृष्ठ संख्या-1)। बैन एंड कंपनी के अनुसार, भारत में लगभग 15.7 मिलियन महिला-संचालित उधम हैं, जो समग्र उधमशीलता परिदृश्य का 22 प्रतिशत है, यह आंकड़ा आगे समर्थन और प्रोत्साहन के साथ 30 मिलियन तक बढ़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, महिला उधमी नवाचार और विविधता के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं, जो नए दृष्टिकोण और समस्या-समाधान के तरीकों को सामने लाती हैं (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-16)। नेटवर्किंग और मेंटरशिप में शामिल होने की उनकी इच्छा समावेशी समुदायों को बढ़ावा देती है जो उधमिता में महिलाओं को अपनाते हैं।

महिला उधमी प्रौद्योगिकी, व्यक्तिगत देखभाल, खाद्य और पेय पदार्थ, फैशन और यहां तक कि रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक रूप से सीमित भूमिकाएं निभाती हैं, मुख्य रूप से प्रशासनिक या सहायक पदों पर। हालांकि, हाल के वर्षों में, इस पुरुष-प्रधान उद्योग में अपनी पहचान बनाने वाली महिला उधमियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रीजा सेबेस्टियन करीमपनल, मंजू याग्रिक, कनिका

गुप्ता शोरी और निरुपा शंकर जैसे प्रमुख नाम रियल एस्टेट में अग्रणी हैं, जो इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए उपलब्ध अवसरों की व्यापकता को प्रदर्शित करते हैं। हालाँकि, प्रगति के बावजूद, भारत में महिला उद्यमियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पक्षपातपूर्ण धारणाएँ, फंडिंग और नेटवर्क तक सीमित पहुँच और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उद्यमशीलता के प्रयासों के साथ संतुलित करने का संघर्ष शामिल है (विश्व बैंक 2024, पृष्ठ संख्या-1)। वरिष्ठता और कार्यकाल के मामले में महिलाओं की उन्नति हमेशा पुरुषों के समान गति से नहीं होती है, जो लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। भविष्य को देखते हुए, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भारत के आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से गति देने की क्षमता रखती है। उद्यमिता में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है जो महिलाओं के लिए समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देता है।

रोजगार सृजन में महिला उद्यमिता का योगदान

महिला उद्यमी नवाचार और लचीलेपन की उज्ज्वल किरण बनकर उभर रही हैं, उद्योगों को बदल रही हैं और अपने दूरदर्शी नेतृत्व से बाधाओं को तोड़ रही हैं। उनके उद्यम केवल व्यवसाय नहीं हैं; वे दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और सशक्तिकरण की शक्तिशाली कहानियाँ हैं, जो अनगिनत अन्य लोगों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती हैं। देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, स्टार्टअप इंडिया पहलों, योजनाओं, सूक्ष्म नेटवर्क और समुदायों के निर्माण और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से भारत में महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)। 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक गेम-चेंजर रही है। 1 अक्टूबर, 2024 तक, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कम से कम एक महिला निदेशक वाली कुल 73,151 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। यह सरकार द्वारा समर्थित 1,52,139 स्टार्टअप में से लगभग आधे का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

विश्व बैंक के एक नए अध्ययन में पता चला है कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने से महिला कर्मचारियों की संख्या काफी हद तक बढ़ सकती है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार के ज़रिए महिलाओं के लिए अधिक मौके पैदा करके न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है बल्कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को भी सशक्त किया जा सकता

है (विश्व बैंक 2024, पृष्ठ संख्या-1)। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहाँ महिलाओं की आधी आबादी होने के बाद भी बिज़नेस जगत में उनके पास पाँचवें हिस्से से भी कम का मालिकाना हक हो। ये सच्चाई है जिसे वर्ल्ड बैंक ने 2006 से 2018 तक 138 देशों में किए गए एक सर्वे में उजागर किया है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सुनिश्चित कर लिया है कि सभी नीतिगत पहलों में महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने, महिला उद्यमियों का महत्व जानने पहचानने और देश की प्रगति और समृद्धि में उनकी आर्थिक भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार ऋण, बाज़ारों और प्रशिक्षणों तक महिलाओं को पहुँच दिलाकर उन्हें देश की उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र में अग्रिम भूमिका देने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का कार्य सहभागिता अनुपात 25 प्रतिशत है। यानी कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। महिला भागीदारी के कम होने का सबसे आबदी वजह पूँजी का नहीं होना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कुटीर और लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा पहली शर्त है। महिला उद्यमिता मूल्य संवर्धन, रोज़गार सृजन, आय के समानता आधारित वितरण और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-29)।

एमएसएमई मंत्रालय कुटीर एवं लघु उद्योगों में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने का प्रयास लगातार कर रही है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की सरकारी ख़रीद नीति 2012 के अनुसार यह अनिवार्य है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी कुल ख़रीद में से तीन प्रतिशत ख़रीद महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई उद्यमों में करनी होगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 में कुल 2.59 लाख महिला उद्यमियों को नए कुटीर एवं लघु उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी देकर समर्थन उपलब्ध कराया जा चुका है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होगा। सूक्ष्म उद्यमशीलता महिला सशक्तिकरण को मजबूत और लैंगिक असमानता को दूर कर रही है (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-32)। एमएसएमई मंत्रालय का लघु ऋण कार्यक्रम महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है। महिला उद्यमी का प्रभाव चैन रीएक्शन की तरह होता है यानी कि एक महिला उद्यमी दूसरे महिलाओं को भी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करती है।

भारत में उद्यमी भूमिकाओं में महिलाओं का उदय न केवल आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनके अभिनव प्रयास, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ, उद्यमशीलता के परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं और अधिक न्यायसंगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे-जैसे महिलाएँ बाधाओं को पार करती हैं और बाधाओं को तोड़ती हैं, सशक्तिकरण की ओर उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। बिहार में महिला उद्यमियों का महत्व आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत

है। महिला उद्यमिता में तेजी लाकर भारत 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यम बना सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी (नीति आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। भारत कार्यबल में 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल करके जीडीपी वृद्धि को 1.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। इससे परिवार की आय में भी स्थायी वृद्धि होगी। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए पीएलएफएस के अनुसार, पुरुषों की 60 प्रतिशत एलएफपीआर की तुलना में महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 41 प्रतिशत है। महिला उद्यमी डिजिटल और सामाजिक प्लेटफार्मों का उपयोग करके वैश्विक बाजार में भी प्रवेश कर रही हैं। महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को उद्यमशीलता की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करके (विश्व बैंक 2024, पृष्ठ संख्या-1)। मिश्रित वित्त तंत्र जैसे कि पहले नुकसान की चूक की गारंटी, बीज पूंजी और कम ब्याज दर पर ऋण का मिश्रण इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। निवेशक समुदाय को लिंग आधारित वित्तीय पहुँच के प्रति संवेदनशील बनाना और महिला उद्यमियों के लिए ऊष्मायन और त्वरण अवसरों के संदर्भ में क्षमता निर्माण भारत में महिला उद्यमिता को मुख्यधारा में लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की ट्रेकिंग और बेंचमार्किंग की अनुमति देने के लिए उपयुक्त डेटासेट की भी आवश्यकता है। देश भर में प्रभावी मेंटरशिप मॉडल को दोहराना सर्वोत्तम प्रथाओं को बेंचमार्क करने और उनसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा संचालित सरकार के नेतृत्व वाली पहलों की भूमिका महिला उद्यमियों के लिए संस्थागत समर्थन को मजबूत करेगी। इसके अलावा, अगर हम महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमशीलता क्रांति को शक्ति देना चाहते हैं तो विभिन्न चैनलों पर आईसीटी और राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से रोल मॉडल का जश्न मनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण होगा। आगे की राह कठिन हो सकती है लेकिन लंबे समय में सार्थक है (योजना मैगज़ीन 2022, पृष्ठ संख्या-19)। महिला उद्यमियों की पूरी क्षमता का दोहन नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है। इस संक्षिप्त विवरण में भारत की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है और उन कारणों की पहचान की गई है जो देश में महिला उद्यमिता की कम दर को स्पष्ट करते हैं। इन बाधाओं को पार करना व्यक्तिगत महिलाओं के लिए खुद के साहस और जुनून का मामला है, साथ ही बाहरी वातावरण में संरचनात्मक कारकों से निपटना भी है, जिस पर उनका अकेले सीमित नियंत्रण है। तदनुसार, यह लेख पाँच अनुशंसाओं पर आता है, जो महिलाओं को उद्यमशीलता के अवसरों को भुनाने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले, महिलाओं की कम उद्यमिता दर आर्थिक भागीदारी और अवसर में व्यापक लैंगिक अंतर का हिस्सा है। इसलिए, शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना और महिलाओं

को कार्यबल में शामिल होकर अपने अर्जित कौशल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ और नेतृत्व पदों पर अधिक महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से नीतियों की आवश्यकता है और इससे महिलाओं को अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो बदले में उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाएगा (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-22)।

भारत में महिला उद्यमियों को वित्त और नेटवर्क तक बेहतर पहुँच की आवश्यकता है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच, महिला उद्यमिता के लिए उत्प्रेरक और ज़ोन स्टार्टअप इंडिया द्वारा शुरू की गई तकनीक में महिलाओं के लिए त्वरक जैसे संगठन महिला उद्यमियों के लिए समर्पित सहायता प्रदान करते हैं। वे उन्हें अपने उद्योग में प्रासंगिक लोगों से जोड़ते हैं और महिला उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देते हैं, ताकि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें। इसके अलावा, वे पिच करने का तरीका सिखाकर और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़कर धन उगाहने में सहायता करते हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि संपार्श्विक बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ वित्त तक समान पहुँच में सुधार कर सकती हैं (IGNOU 2024, पृष्ठ संख्या-8)।

योग्य महिलाओं को बनाए रखने में मदद करने के लिए अधिक समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में। सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में सुधार के उपाय आवश्यक हैं, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा के बारे में हमेशा चिंता करने के मानसिक बोझ के बिना अपने घरों और कार्यालयों के बीच आवागमन कर सकें। महिला उद्यमियों को अपनी उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवारों और सामाजिक हलकों से अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। घरेलू और देखभाल संबंधी कर्तव्यों को महिलाओं की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, महिला उद्यमियों को मातृत्व लाभ प्रदान करना, बच्चों की देखभाल में सुधार करना और सामाजिक स्वीकृति पैदा करना उन्हें अपनी उद्यमशीलता की गतिविधियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक साथ लाने में मदद करेगा (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

महिला सशक्तिकरण एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो केवल लैंगिक समानता से परे है। यह एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के बारे में है जहाँ महिलाएँ सकारात्मक बदलाव के लिए सक्रिय भागीदार, नेता और उत्प्रेरक हों। अपने अधिकारों की वकालत करने से लेकर शिक्षा और करियर के अवसरों को आगे बढ़ाने तक, महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाना आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका नेतृत्व, लचीलापन और रचनात्मकता समाज और राष्ट्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (योजना मैगज़ीन 2023, पृष्ठ संख्या-16)। महिलाएँ कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाती हैं और उद्योगों

में नवाचार और विकास में योगदान देती हैं। भारत में, महिला उद्यमी देश को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

निष्कर्ष

भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है और महिला उद्यमी, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत के 63 मिलियन एमएसएमई में से लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो 22 से 27 मिलियन महिलाओं और पुरुषों को रोजगार देती हैं। महिलाओं की बढ़ी हुई आर्थिक भागीदारी जीडीपी को बढ़ावा देती है और सतत विकास, लैंगिक समानता और गरीबी में कमी को बढ़ावा देती है। अनुमान बताते हैं कि 2025 तक कार्यबल में 68 मिलियन महिलाओं को जोड़ने से भारत की जीडीपी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ सकती है और कार्यबल में 50 प्रतिशत अधिक महिलाओं को शामिल करने से जीडीपी वृद्धि 1.5 प्रतिशत अंकों तक बढ़ सकती है। इसलिए, भारत सरकार के आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। भारत के उभरते आर्थिक परिदृश्य में, महिला उद्यमी तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और ऐसे अपरिहार्य योगदान दे रही हैं, जिन्हें उचित मान्यता मिलनी चाहिए। ये गतिशील महिला उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं, रोजगार सृजन, विकास में तेजी और समग्र समृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं।

भारत की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अנוखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से 45 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं सिर्फ इसलिए व्यवसाय शुरू करती हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है। महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई या MSME, पुरुषों के स्वामित्व वाले उद्यमों से अलग होते हैं और आर्थिक झटकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे घरेलू ज़िम्मेदारियों को निभाने, सीमित कौशल, सीमित नेटवर्क पहुंच और फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों से जूझती हैं। महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों का वार्षिक कारोबार पुरुषों के स्वामित्व वाले व्यवसायों की तुलना में केवल 59 प्रतिशत है। सुरक्षा और गतिशीलता संबंधी चिंताएँ महिला उद्यमियों को बाजारों तक पहुंचने से रोकती हैं। कई मामलों में, परिवार के पुरुष सदस्य व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण रखते हैं। ये चुनौतियाँ, सामाजिक मानदंडों के साथ मिलकर महिलाओं की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को दबा देती हैं। महामारी के प्रभाव और तेज़ डिजिटलीकरण की ज़रूरत ने इन कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है।

महिलाओं के उद्यमिता के सफर के महत्वपूर्ण चरणों में एमएसएमई को निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जीवित रहें, आगे बढ़ें और लचीले बनें। उद्यमियों को उद्यमों के अस्तित्व और विकास का

समर्थन करने के लिए निरंतर व्यावसायिक सहायता सेवाओं की आवश्यकता होती है। नीति निर्माता एक जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाकर इसे बेहतर बना सकते हैं जो ऊपर बताई गई छह मौलिक पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आवश्यकताओं के साथ संरेखित होता है और खंडित योजनाओं को एकीकृत करता है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं को एकीकृत करने से वित्त, इनक्यूबेशन, हैंडहोल्डिंग, मार्केट लिकेज और उच्च-क्रम सहायता सेवाओं को संबोधित किया जा सकता है। उद्यमी जीवनचक्र में एकीकृत योजनाएँ अकेले पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। सरकारों को सभी सहायता कार्यक्रमों तक सुविधाजनक अंतिम-मील पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए और डिजिटल और भौतिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। एक "फ्रिजिटल" मॉडल जो भौतिक और डिजिटल जुड़ाव को जोड़ता है, निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए सबसे अच्छा काम करेगा, नामांकन को सुविधाजनक बनाने और अंतिम-मील पहुँच प्रदान करने के लिए गाँव-स्तरीय फ्रंटलाइन बल की सहायता से।

संदर्भ सूची

- नीति आयोग (2024), महिला उद्यमियों को सरकारी मदद, <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Decoding-Government-Support-to-Women-Entrepreneurs-in-India.pdf>
- अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2024), भारत में महिला उद्यमी: उन्हें क्या रोक रहा है?, URL: <https://www.orfonline.org/research/women-entrepreneurs-in-india-what-is-holding-them-back>
- अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2024), भारत के पूर्वोत्तर में महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल समाधान अपनाना, URL: <https://www.orfonline.org/expert-speak/embracing-digital-solutions-for-women-entrepreneurs-in-india-s-northeast>
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024), महिलाएं व्यवसाय शुरू करने में आने वाली बाधाओं को तोड़ने के लिए संघर्ष करती हैं, URL: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/03/womens-entrepreneurship-in-India-mathew>
- फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन एंटरप्रेन्योर्स (FIWE) 2024, देश की प्रगति में महिला उद्यमिता, URL : <https://fiwe.org/>
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (2024), भारत की महिला उद्यमी समावेशी विकास और समान वृद्धि की अग्रणी, URL: <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2082821>
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2024), एमएसएमई में महिला उद्यमी, URL: <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2002848>
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2024), महिला उद्यमिता विकास और आर्थिक सशक्तिकरण, URL: <https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/women-entrepreneurship-development-and-economic-empowerment>

9. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (2024), भारत में महिला उद्यमिता,
URL: https://www.startupindia.gov.in/hindi/content/sih/en/women_entrepreneurs.html
10. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (2024), महिला उद्यमियों की अग्रणी भूमिका,
URL: <https://www.rojgarsamachar.gov.in/NewRS/MoreContentNew.aspx?n=InDepthJobs&k=10098>
11. विश्व बैंक (2024), भारत में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए उम्मीद की नई किरण,
URL: <https://www.worldbank.org/hi/news/feature/2019/03/31/social-impact-bond-help-women-entrepreneurs-india>
12. सिलवाल, कविता (2023), “लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में महिला उद्यमी की भूमिका”, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ऐडवांसड इन सोशल साइयन्स, वॉल्यूम-1, संख्या-2, पृष्ठ संख्या- 1-9
13. इग्नू (IGNOU) 2024, उद्यमिता के आयाम,
URL: <https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/88724/1/Unit-3.pdf>
14. अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), सोशल कॉमर्स और महिला उद्यमशीलता: लचीले विकास की पूर्व-शर्त,
URL: <https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/women-in-social-commerce-tailwind-to-a-resilient-growth>
15. अब्जर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2024), महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय तकनीक की शुरुआत हो,
URL: <https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/womens-entrepreneurship-in-india-fintech-lending>
16. कुरुक्षेत्र मैगज़ीन (2020), महिला उद्यमियों हेतु अवसर और चुनौतियां,
URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
17. कुरुक्षेत्र मैगज़ीन (2020), सशक्त ग्रामीण महिला उद्यमियों से नए भारत का सृजन, URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
18. कुरुक्षेत्र मैगज़ीन (2020), सशक्त ग्रामीण महिला उद्यमियों से नए भारत का सृजन,
URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
19. कुरुक्षेत्र मैगज़ीन (2019), सशक्त महिला सशक्त समाज,
URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
20. योजना मैगज़ीन (2023), भारत में महिला उद्यमिता : एमएसएमई क्षेत्र,
URL: https://afeias.com/knowledge-centre/magazines/yojana_29-04-2023/
21. योजना मैगज़ीन (2023), अमृतकाल में भारतीय एमएसएमई के लिए अवसर,
URL: https://afeias.com/knowledge-centre/magazines/yojana_22-04-2023/
22. योजना मैगज़ीन (2023), महिला उद्यमिता आर्थिक सशक्तीकरण का जरिया,
URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
23. योजना मैगज़ीन (2018), महिला का आर्थिक सशक्तीकरण,
URL : <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>
24. योजना मैगज़ीन (2023), महिला सशक्तीकरण हाल के सुधार,
URL: https://afeias.com/knowledge-centre/magazines/yojana_30-09-2023/
25. योजना मैगज़ीन (2022), आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण,
URL: https://afeias.com/knowledge-centre/magazines/kurukshestra_16-04-22/
26. योजना मैगज़ीन (2022), महिला सशक्तीकरण: सरकार का दृष्टिकोण,
URL: <https://afeias.com/knowledge-centre/magazines>